(ख) प्रत्येक योजना की वर्तमान अवस्था क्या है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा उसकी स्वीकृति कब तक दे दी जाएगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) और (ख) मध्य प्रदेश की गई बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया है। **[देखिए परिशिष्ट 178, अनुपत्र संख्या 17]**

पटना और इलाहाबाद के बीच जलमार्गों को खोलना

406. **श्री नागमणि:** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पटना और इलाहाबाद के बीच जल मार्ग को यातायात के लिए अभी तक नहीं खोल पाई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह जल मार्ग परिवहन और यातायात के लिए कब तक खोल दिया जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी० जी० वेंकटरामन) (क) से (ग) पूर्ण ज्वार की अवधि में पटना और इलाहाबाद के बीच जलमार्ग यातायात के लिए खुला रहता है। तथापि, इसे पूरे वर्ष भर नौचालन योग्य बनाने के लिए, तल विनियमन संबंधी कार्यकलाप, जैसे निकर्षण, बैंडलिंग और टर्मिनल सुविधाओं हेतु प्रावधान को नौवीं पंच वर्षीय योजना में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है और इन्हें कार्गो की बढ़ोत्तरी और निधियों की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध किया जाएगा।

सिंचाई परियोजनाओं में विदेशी ऋणों का कम मात्रा में उपयोग किया जाना

407. **श्री राम जेठमलानी:** क्या **संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में अनेक सिंचाई परियोजनाएं अभी निर्माणाधीन हैं, जिनके लिए विदेशों से कर्ज लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1996 तक ऐसी कुल कितनी परियोजनाएं थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब होने के कारण, स्वीकृति विदेशी कर्ज की राशि का उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो कुल स्वीकृत धनराशि कितनी है तथा अनुपयोगित राशि कितनी है जिस पर सरकार को बचनबद्धता प्रभार देना पड़ रहा है; और

(ङ) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान सरकार ने वर्ष-वार बचनबद्धता प्रभार की कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) जी, हां।

(ख) मार्च, 96 तक देश में सिंचाई से संबंधित ऐसी 30 परियोजनाएं हैं, जिनका कार्यान्वयन विश्व बैंक और विदेशों की सहायता से किया जा रहा है।

(ग) कुछ परियोजनाओं में निर्माण में परिवर्तन और अन्य बाधाओं के कारण विदेशी ऋण के उपयोग में कुछ विलम्ब हुआ है।

(घ) और (ङ) वर्ष 1993-94 और 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान कुछ परियोजनाओं के लिए ऋण की कुल स्वीकृत राशि और प्रयोग में न लाए गए ऋणों पर प्रतिबद्धता प्रभारों को दर्शाने वाला विवरण साथ लगा है।

विवरण

सिंचाई परियोजनाओं में विदेशी ऋण का उपयोग न किए जाने के संबंध में ब्यौरा

क्रम सं०	परियोजना का नाम	राज्य डोनर करेंसी में संस्वीकृत राशि (मिलियन में) (कोष्ठक में दिए गए मिलियन रुपए के बराबर)		प्रतिबद्धता प्रभार (आंकड़े हजार रुपए में)		
				1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5	6	7
1.	बांध सुरक्षा आश्वासन और पुर्नस्थापन परियोजना	बहु-राज्यीय	अम० डालर 148.884 (5210.94)	1810	1810	1031
2.	अपर कृष्णा चरण-II	कर्नाटक	अमरीकी डालर 169.288 (5922.28)	3947	3567	3765

1	2	3	4	5	6	7
3.	लघु सिंचाई परियोजना	राजस्थान	ब्यूरा मार्क 12.300 (282.16)	390.05	269.665	186.748
4.	उड़ीसा लिफ्ट सिंचाई	उड़ीसा	ब्यूरा मार्क 95.00 (1261.7)	1536.913	2455.613	2862.495
5.	माजलगांव सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	फ्रेंच फ्रेंक 3.050 (20.748)	—	370.317	3.172
6.	जल वितरण प्रणाली का मानचित्रण और नियंत्रण	दिल्ली	फ्रेंच फ्रेंक 1.600 (10.884)	21.408	—	—
7.	फलार बेसिन में जल स्तर में कमी का अध्ययन	कर्नाटक	फ्रेंच फ्रेंक 3.350 (22.789)	—	10.075	—

Crisis in Subsidiaries of National Textile Corporation

408. SHRI MOHINDER SINGH KALYAN: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether the subsidiaries of the National Textiles Corporation are facing a serious crisis due to lack of competent managerial staff;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the measures taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI R.L. JALAPPA): (a) to (c) No, Sir, NTC has been suffering losses due to various reasons like obsolete machinery, excess man-power high cost of raw material, acute shortage of working capital etc. On account of continuous loses suffered by NTC mills, 8 out of its 9 subsidiaries have been referred to the BIFR which has declared them to be sick industrial companies. Government has approved a revised modernisation plan for NTC Mills. The plan envisages modernisation of 79 mills at an outlay of Rs. 2005.72 crores, restructuring of 36 unviable mills into 18 viable units, rationalisation of surplus workforce through Voluntary Retirement Scheme, etc. The plan will be implemented after approval by BIFR. Meanwhile to avoid hardship to the workers, Government are meeting the shrotfall faced by NTC in payment of wages/salaries to workers employees of NTC.

Cotton Imports

409. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) the quantity and value of cotton likely to be imported during the current year;

(b) the impact of this import in domestic market; and

(c) the concrete steps taken to minimise the import of cotton?

MINISTER OF TEXTILES (SHRI R.L. JALLAPA): (a) The Cotton Advisory Board in its meeting held on 17.6.96 has estimated likely imports of cotton for the year (September 95—August 96) at 1 lakh bales. These are estimated to be valued at Rs. 120 crores approximately.

(b) and (c) Cotton imports are under Open General License. (OGL) with zero import duty. Import is made either under the Advance Licensing Scheme or by 100% EOUs or by textile mills to meat[1] specific quality requirements depending on relative price, and demand and supply position. The current level of imports are not expected to have any adverse impact on the domestic market.